Volume : 2 | Issue : 11 | Nov 2013 • ISSN No 2277 - 8160

Research Paper | Political Sciencet

राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ
Rashtra ke Samaksh Chunautiyaa

Dr. Surya Bhan Singh

Assistant Professor & Co-ordinator Deptt. Of Political Science, Uttarakhand open University, Haldwani ,Nainital(263139)

ABSTRACT

किसी भी देष को मजबूती तब मिलती है जब उसके विभिन्न पक्ष उत्तरोत्तर प्रगति की और अग्रसर होते है समाज में यदि कोई पक्ष विकास की मुख्य धारा से वंचित हो जाता है तो राश्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है इसके साथ ही यह भी आवष्यक होता है की देष के आतंरिक प्रषासन का सुचारू संचालन हो और राजनीतिक गतिविधियां तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए संचालित न होकर देष को मजबूती देने वाली और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो यदि ऐसा होगा तभी परराश्ट्र संबंधों का संचालन अर्थात विदेष नीति का संचालन भी हम मजबूती के साथसाथ कर पाते है लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि देष के अंदर नक्सालवाद जैसी आतंरिक समस्या के साथ ही महगाई जिसका कारण भ्रस्टाचार है आम आदमी का जीवन कठिन कर दे रहा है तो दूसरी तरफ हम अपनी विदेष नीति के संचालन पर प्रष्न चिन्ह लग रहा है क्योंकि हम चाहे चीन हो पकिस्तान हो नेपाल में बढता माओवाद हो या श्रीलंका की तमिल समस्या हो जिससे हम सीधे तौर से भावनात्मक रूप से जुड जाते है परन्तु कोई रचनात्मक पहल नहीं कर पा रहे है इन्ही पक्षों का अध्ययन इस लेख में किया गया है

KEYWORDS : राश्ट्र,लोकतंत्र, कल्याणकारी, सषक्तिकरण, संसदीय लोकतंत्र, संघात्मक षासन

राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ – इस समय देष के अंदर बहुत सी समस्याएं है जैसे बढ़ती गरीबी ,देष के विभिन्न क्षेत्रों में बढती असमानता ,देष के विभिन्न समुदायों के बीच बढती असमानता ,देष की आजादी के 65 वर्श बीत जाने के बाद भी कल्याणकारी योजनाओं पर ही बल।उसके साथ अपने राजनीतिक स्वार्थ को जोडते हुए षासन दिखाई दे रहा है।, सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में प्रारम्भ हुआ नक्सलवादी आंदोलन आज राजन. ैतिक समस्या बन गया है पेट्रोलियम उत्पादों के बढती कीमतें ,इन बढती कीमतों के कारण आम आदमी पर पड़ने वाले महगाई के बोझ।हमारी व्यस्था में महगाई से बचने के लिए सार्वजनिक रोंजगार में रहने वाले को प्रति छः माह पर 7 से 10 प्रतिशत की बृद्धि महगाई के रूप में देते है लेकिन उन किसानों के लिए क्या है जो धरती का सीना चीरकर देष को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाए लेकिन खुद को परनिर्भर ही पाते हैं।खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागत योग्य है क्यों कि जीने का अधिकार अपने देष में सभी के पास हो यह लोकतंत्र की मांग है परन्तु यह बेहद दुःख का विशय है कि आजादी के 65 वर्श बीत जाने के बाद भी हम अभी भी प्रति माह 5 किलो अनाज देने की सोच की जकडन में फंषे है।अब तक तो हमें विकास के वो मुकाम छूने थे कि ,अब जो नीतियां बनती और कार्यक्रम लागू किये जाते वे कल्याणकारी न होकर सषक्तिकारी होते ।फिर लोकतंत्र में जो सरकार के भाग्य विधाता हों, वे स्वयं सरकार के द्वारा दिए जाने वाली कृपा राषि पर जीवन जिए ,यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है ।

देष में विभिन्न राज्यों में बढ़ती असमानता ने छोटे राज्यों की मांग को और प्रबल किया है यह स्वाभाविक भी है क्यों बड़े राज्यों में संख्या बल में छोटे समुदायों को सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यदा–कदा लोकतंत्र तो अंकों के खेल के रूप में दिखाई देने लगता है।बड़े राज्यों में किसी एक क्षेत्रों की जनता यदि असंतुश्ट है तो दूसरे क्षेत्र की जनता का समर्थन मिलने की संभावना रहती है।जबकि छोटे राज्यों में ऐसी संभावना बहुत कम ही होती है।इसलिए छोटे राज्यों के गठन को लेकर उन्हें समर्थन के विशय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।हमारी समझ में तो उन्हें समर्थन भी करना चाहिए।परन्तु समर्थन के उन क्षेत्रो की मांगो से जुड़े समुदायों से अपने को जोड़कर स्वयं इन मांगों का नेतृत्व करना चाहिए । इसमें इससे जुडी एक षंका का निवारण करना भी आवष्यक प्रतीत हो रहा है।छोटे राज्यों से देष की एकता और अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।इस सम्बन्ध में यह पक्ष रखना गलत है क्यों कि ये राज्य संविधान द्वारा निर्धारित सीमा,अपने अधिकारी और षक्तियों के दायरे में रहकर कार्य करेंगे।

हमारे देष में संविधान के द्वारा संसदीय लोकतंत्र के साथ संघात्मक षासन को अपनाया गया है।संसदीय लोकतंत्र इसलिए कि देष के सभी समुदायों को केंद्र की सरकार में भागीदारी प्राप्त हो से। इसी में यह संभव है।क्योंकि इसमें कार्यपालिका मंत्रिपरिशद होती है।जब कि अध्यक्षात्मक षासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष एक मात्र व्यक्ति होता है । यदि यह षासन अपने जाता तो सभी को संघ की सरकार में भागीदारी संभव नहीं थी। यहाँ हम यह भी स्पश्ट करना चाहते है की ऐसा प्रतीत होता है कि संसदीय षासन को अपनाया गया जिससे देष के सभी भागों को जैसे सभी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र अर्थात सभी हितों को षासन में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो सके।जिससे नीति निर्माण में उन हितों को षामिल किया जा सके।जो परंपरागत रूप से उपेक्षित और वंचित रहे है।यदि ऐसा हुआ होता तो निष्चित रूप से आज देष में इस तरह की विघटनकारी प्रवृत्तियाँ को पनपने का अवसर न प्राप्त होता जो आज देष के आतंरिक प्रषासन के संचालन में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। इसके परिणाम यहीं तक सिमित नहीं है।आज देष में घटने वाली बहुत सी घटनाओं में यह पाया जा रहा है कि देष के ये विघटनकारी तत्व वाह्य आतंकी तत्वों के साथ भी गठजोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो देष के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है।जिसका यदि समय रहते निराकरण नहीं किया गया तो इसके दूरगामी परिण ाम बहुत ही विनाषक होंगे।इसके लिए हमें एक साथ कई मोर्चों पर कार्य करने की आवष्यकता है।जैसे एक तरफ तो हमें समाज के उन पक्षों के लिए जो कि आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं, और हम आजादी के 65 वर्श बीत जाने के बाद भी हम बहुत कुछ नहीं कर पायें हैं। उनके सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए व्यापक कार्ययोजनाओं की आवष्यकता है, क्योंकि इसी समुदाय को विघटनकारी तत्व राश्ट्र के विरूद्ध इस्तेमाल करने में सफल होते हैं।यदि हम ऐसा करने में सफल हुए तो निष्चित रूप से वे भी विकास की मुख्य धारा में होंगे और उनका इस्तेमाल कोई भी विघटनकारी कार्यों में नहीं कर सकेगा।यहाँ हम यह भी स्पश्ट करना चाहते हैं कि ये नीतियां कल्याण ाकारी न होकर सषक्तिकरण करने वाली हों,क्योंकि कल्याणकारी नीतियों में तो उन्हें अनवरत सरकार की तरफ देखना ही पडेगा।इस लिए सषक्तिकरण करने वाली नीतियां हो जिसका सफल क्रियान्वयन भी सुनिष्चित किया जाय।जिससे वे भी अपना जीवन एक स्वतन्त्र नागरिक रूप में विता सके। इसके साथ ही साथ विघटनकारी तत्वों के विरुद्द आक्रामक रवैया अपनाते हुए उनके समाप्ति का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि कैंसर का इलाज करते समय उसकी कोषिकाओं के स्वास्थ्य की चिंता इस लिए नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे षरीर में है।

संघात्मक षासन इस लिए अपनाया गया क्यों कि हमारे देष में सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता के भौगोलिक संरचना में भी विविधता पाई जाती है।भौगोलिक संरचना में विविधता उनकी आवष्यकताओं और समस्याओं में भी विविधता भी पाई जाती है।इसके समाधान के रूप में राज्यों का निर्माण पूर्व में किया जा चुका है। वैसे भी बड़े राज्य जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता हो ,राजनीतिक दृश्टि से छोटे समुदायों के लिए और प्रषासनिक दृश्टि भी उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि नीति निर्माण में सभी हितों को षामिल करना संभव नहीं हो पाता है।इस लिए छोटे राज्यों के निर्माण का समर्थन सामाजिक,सांस्कृतिक ,प्रषासनिक और राजनीतिक सभी दृश्टियों से सही प्रतीत होता है। हम यदि संयुक्त राज्य अमेरिका को देखे तो हमारे यहाँ जितनी जनसँख्या केवल षहरों में है लगभग उतनी ही जनसँख्या अमेरिका की है।अमेरिकी संघ के निर्माण के समय उसमें मात्र 13 राज्य थे जबकि वर्तमान समय में इनकी संख्या 52 हो गई है।बावजूद इसके आज अमेरिका एक मजबूत राश्ट्र के रूप में अंतरराश्ट्रीय मंच पर उभरा है।

देष में आज आतरिक समस्याओं के साथ वाह्य चुनौतियां भी कम नहीं है । पुरू करते है पड़ोसी नेपाल से जिसके साम्यवादी नेता अब भारत की यात्रा के पूर्व चीन जान आवष्यक समझते है।वे चीन को नाराज नहीं कर सकते भले ही भारत वर्शों से षर्तरहित सहयोग करता रहा है।चीन पाक अधिकृत कष्मीर तक सुरंग बनाने की नीति पर काम कर रहाहै। हिंदमहासागर ,म्यांमार ,भूटान आदि की तरफ से हमारे देष को घेरने की रणनीति पर कार्य कर रहां है ,जब कि दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलियम के षोध और उत्पादन से भारत को रोकना चाहता है।जब भारत और चीन के बीच व्यापारिक सनदी हुई उसमें यह भी षामिल था कि राजनीतिक मतभेदों को उसी स्थान पर छोडते हुए आर्थिक संबंधो अको आगे बढ़ाया जाए । इसके पीछे विषेशग्यों की राय थी आर्थिक संबंधों के विस्तार के साथ राजनीतिक संबंधों के तनावपूर्ण पक्षों में षिथिलता आयेगी क्योंकि आर्थिक संबंधों के विस्तार की प्रक्रिया में दोनों देषों के जनमानस के बीच आदान प्रदान से उन्हीं के द्व ारा तनाव के पक्षों का समाधान करने के लिए सम्बंधित देष के जनमानस द्वारा दबाव बनाया जाएगा।परन्तु सीमा पर भारत के आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए पहल से चीन की सीमा पर अतिक्रमणकारी गतिविधियाँब बढ़ गई हैं जो बहुत ही चिंताजनक तथ्य है।इसलिए इस बढे हुए आर्थिक सम्बन्ध का प्रयोग चीन पर दबाव बनाने के राजनय पर कार्य करने की जरूरत है क्यों कि इस बढे हुए आर्थिक सम्बन्ध में व्यापार चीन के पक्ष में है।जिससे भारत भारी व्यापारिक घाटे के बावजूद इस सम्बन्ध को निभा रहा है।यदि हम इस सम्बन्ध को निभा रहे हैं तो हमें अपने हितों के अनुरूप सौदे बाजी भी इस आधार करना चाहिए। आज हमारे देष की आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप स्थिति यह है कि अंतर्राश्ट्रीय मुद्रा बाजार में रूपये के मूल्य में भारी गिरावट देखी गई है।परिण ामस्वरूप चीन की मुद्रा युआन में भी मजबूती देखी जा रही है 2012 में जहां एक युआन की कीमत 8 रूपए थी वहीं आज 11रूपए तक पहुँच गई है। जिससे भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार में घाटा और बढ़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारे देष के द्वारा सम्बन्ध को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए पहल करने में जल्दबाजी दिखाई जाती है जबकि सौहार्द का भाव अपने अंतःकरण में रखना चाहिए।हमें सौहाद के साथ दबाव की राजनीति के लिए अपने कूटनीतिक तरकष में तीर बचा के रखना चाहिए क्यों कि चीन माओ को अपना आदर्ष मानता है जो यदि षांत भी है तो यह उसकी रणनीति है न कि स्वभाव क्योकि वह जब सबसे मजबूत स्थिति में होता है तब, जिसे वह अपना षत्रु मानता है उसके प्रति आक्रामक रवैया अपनाता है । जब वह कमजोर स्थिति में हो

तब अपने असली चरित्र को सामने नहीं लाता है।इसलिए हमें भी जैसा देष वैसी नीति की रणनीति पर कार्य करना चाहिए यही बात पकिस्तान के सन्दर्भ में भी लागू होती है।

निष्कर्श – उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते है हैं कि आज देष के समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं।जिनका समय रहते निराकरण नहीं किया गया तो यह बहुत ही विनाषक परिणाम लेकर आयेगा इस लिए आवष्यकता इस बात की है कि सबसे पहले हम उन समस्याओं को उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करे तभी उनके निराकरण हेतु सही उपचार किया जा सकता है।आज हमारे देष में भ्रश्टाचार के कारण बढती महगाई के निराकरण के लिए, पहले भ्रश्टाचार पर अंकुष लगाना होगा।साथ ही विघटनकारी तत्वों से निपटने के लिए देष के षासन में सभी हितों को संवैधानिक सीमा में रहते हुए भागीदारी देने साथ–साथ प्रगति के विकेन्द्रित मॉडल को व्यवहारिक धरातल पर उतारना होगा।जिसमें कल्याण नहीं वरन लोकतंत्र की भावना अनुरूप सषक्तिकरण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा ।

REFERENCES

1.ब्रज किषोर षर्मा – भारतीय संविधान, 2.डी.डी. बासु– भारतीय संविधान एक परिचय, 3.बेयर एक्ट ... भारतीय संविधान ,दैनिक समाचार पत्र– दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिदुस्तान, उत्तर उजाला, ज्पउमे वि ंदकपं एकुरुक्षेत्र, योजना।